SHAKTI®
PUMPING LIFE

Date: -02.09.2020

To,
The Manager,
Listing Department
The National Stock Exchange of India Ltd.
Exchange plaza, BKC, Bandra (E)
Mumbai-MH 400051.

To,
The Manager,
Listing Department
The BSE Ltd.
P.J. Towers, Dalal Street
Mumbai- MH 400001.

REF: - (ISIN- INE908D01010) SCRIP CODE BSE-531431, NSE Symbol-SHAKTIPUMP

Sub: -Submission of copies of Newspaper advertisement in respect to publication of Notice of 25th Annual General Meeting through Video Conferencing/Other Audio Visual Means.

Dear Sir,

Pursuant to Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligation and Disclosure Requirement) Regulations 2015, Please find enclosed copies of newspaper publication published in Free press, Indore (English) Business Standard, Indore/Bhopal (Hindi) dated 31st August 2020, for 25th Annual General Meeting which will be held on Tuesday, 29th September 2020 at 12:30 P.M. through Video Conferencing ("VC")/ Other Audio Visual Means ("OAVM")

You are requested to please take on record our above said information for your reference.

Thanking you,

Yours faithfully,
For Shakti Pumps (India) Limited

Ravi Patidar
Company Secretary

SHAKTI PUMPS (INDIA) LIMITED

CIN: L29120MP1995PLC009327, **Regd. Office & Works:** Plot No. 401, 402 & 413, Industrial Area, Sector - 3, Pithampur - 454774, Dist. Dhar (M.P.) INDIA.
Tel.: +91 7292 410500, **Fax:** +91 7292 410645, **E-mail:** info@shaktipumps.com, sales@shaktipumps.com, **Web:** www.shaktipumps.com

संक्षेप में

जरूरी चीजों को तरजीह दे रहे उपभोक्ता : नेस्ले

दैनिक उपयोग का सामान बनाने वाली कंपनी नेस्ले इंडिया के चेयरमैन सुरेश नारायण ने कहा है कि कोविड-19 महामारी के बीच उपभोक्ताओं के व्यवहार में बड़ा बदलाव आया है और अब वे लक्जरी की जगह जरूरी चीजों की खरीदारी को प्राथमिकता दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस संकट के चलते पैदा हुए आर्थिक व्यवधान के कारण उपभोक्ता खर्च के तरीके में बदलाव हुआ है और अब गुणवत्ता, सुरक्षा, पोषण तथा भरोसे को अधिक महत्व मिल रहा है, क्योंकि अनिश्चितता के इस वक्त में उपभोक्ता जांचे-परखे ब्रांडों को पसंद कर रहे हैं। नारायण ने कहा कि कोविड-19 के बाद आर्थिक संकट के कारण उपभोक्ताओं के खर्च करने के तरीके में बदलाव आया है, और अब लक्जरी की जगह जरूरी चीजों की खरीदारी को प्राथमिकता दी जा रही है। इसके साथ ही उपभोक्ता अब ई-कॉमर्स जैसे माध्यमों का अधिक इस्तेमाल कर रहे हैं और लॉकडॉउन के पहले के मुकाबले इनका प्रसार बढ़ा है। *भाषा*

रीट में म्युचुअल फंडों का निवेश तीन गुना बढ़ा

निवेश के उभरते माध्यम रियल एस्टेट निवेश न्यास (रीट) में म्युचुअल फंडों का निवेश इस साल की पहली छमाही में तीन गुना होकर 735 करोड़ रुपये पर पहुंच गया। हालांकि इस दौरान बुनियादी संरचना निवेश न्यास (इनविट) में म्युचुअल फंडों का निवेश आठ फीसदी गिरकर 4,968 करोड़ रुपये रह गया। बाजार नियामक भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) के आंकड़ों में इसकी जानकारी मिली है। भारतीय संदर्भ में रीट और इनविट निवेश के काफी नए माध्यम हैं, लेकिन विदेश में ये काफी लोकप्रिय हैं। *भाषा*

दूरसंचार उद्योग की आय 14-15 फीसदी बढ़ेगी

दूरसंचार उद्योग की आय में चालू वित्त वर्ष (2020-21) में 14 से 15 फीसदी की वृद्धि की उम्मीद है। दूरसंचार कंपनियों के संगठन सेल्युलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (सीओएआई) ने यह अनुमान लगाया है। सीओएआई ने कहा कि ऑपरेटर की प्रति ग्राहक औसत कमाई (एआरपीयू) कुछ बढ़ी है, जिससे उनके कुल राजस्व में बढ़ोतरी की उम्मीद है। हालांकि, वित्त वर्ष के दौरान मोबाइल कनेक्शनों की संख्या पहले के स्तर पर ही बने रहने का अनुमान है। *भाषा*

डिजिटल समाधानों से महामारी में नियुक्ति संभव

बुनियादी ढांचे की दिग्गज घरेलू कंपनी लार्सन ऐंड टुब्रो (एलऐंडटी) ने कहा कि नवोन्मेषी डिजिटल समाधानों के कारण कोविड-19 महामारी के दौरान भी नियुक्ति करना संभव हो पाया। कंपनी ने कहा कि उसने इन समाधानों की मदद से आईआईटी जैसे संस्थानों और सरकारी महाविद्यालयों से 1,297 उम्मीदवारों को काम पर रखा है। *भाषा*

अनिल अंबानी समूह कंपनियों को एनसीएलटी भेजने का मामला

आरबीआई ने बैंक का अनुरोध ठुकराया

देव चटर्जी
मुंबई, 30 अगस्त

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने अनिल अंबानी समूह कंपनियों - रिलायंस होम फाइनैंस लिमिटेड (आरएचएफएल) और रिलायंस कमर्शियल फाइनैंस लिमिटेड (आरसीएफएल) को आईबीसी की धारा 227 के तहत कर्ज समाधान के लिए राष्ट्रीय कंपनी विधि पंचाट (एनसीएलटी) भेजने के बैंक ऑफ बड़ौदा (बीओबी) के प्रस्ताव को ठुकरा दिया है। एक अधिकारी के अनुसार, आरबीआई इन ऋणदाताओं और दोनों कंपनियां द्वारा पिछले साल के 7 जून सर्कुलर के तहत सफल समाधान को लेकर की गई प्रगति से संतुष्ट है।

बीओबी इन दोनों कंपनियों का प्रमुख कंसोर्टियम है और उसने नियामक से इस साल मई में कंपनी को एनसीएलटी में भेजने का अनुरोध किया था। आईबीसी की धारा 227 के तहत वित्तीय सेवा कंपनियों को कर्ज समाधान के लिए एनसीएलटी के हवाले करने के लिए आरबीआई और केंद्र सरकार को विशेष अधिकार हासिल है। बीओबी ने अपना अनुरोध आरबीआई द्वारा ठुकराए जाने के बारे में गुरुवार को शेष ऋणदाताओं को अवगत कराया।

आरबीआई का यह कदम दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश के बाद बीओबी (दोनों कंपनियों का प्रमुख बैंक) के लिए दूसरा झटका है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने 18 अगस्त को इन खातों को धोखाधड़ी के तौर पर वर्गीकृत किए जाने और के लिए बीओबी और ऋणदाताओं और पूरे कंसोर्टियम की पहल पर पर रोक लगा दी।

दिलचस्प है कि जहां ऑडिट फर्म एमके अग्रवाल ऐंड कंपनी द्वारा रिलायंस होम फाइनैंस पर एसबीआई द्वारा कराए गए फॉरेंसिक ऑडिट में अनिल अंबानी समूह की कंपनी को क्लीन चिट दी गई, लेकिन ग्रांट थॉर्न टन द्वारा समान खातों के लिए बैंक ऑफ बड़ौदा के लिए तैयार अन्य फॉरेंसिक रिपोर्ट में होम फाइनैंस कंपनी को फ्रॉड अकाउंट के तौर पर पेश किया गया। इस साल मार्च में, रेटिंग कंपनी केयर ने आरएचएफएल का 11,726 करोड़ रुपये का ऋण डिफॉल्ट श्रेणी में शामिल किया था। जहां अनिल अंबानी कंपनियों और ऋणदाताओं के बीच कानून लड़ाई बरकरार है, वहीं बीओबी के नेतृत्व में कुछ ऋणदाताओं ने आरसीएफ और आरएचएफएल के लिए बोलियां आमंत्रित की हैं जिन्हें 13 संभावित बोलीदाताओं से प्रस्ताव मिले।

ये ईओआई कैपरी ग्लोबल, इंडिया आरएफ, जेएम फाइनैंशियल एआरसी, एडलवाइस एआरसी, यूवी एआरवी, यूजीआरओ कैपिटल, एआरसीआईएल, ऑथम इन्वेस्टमेंट ऐंड इन्फ्रा लिमिटेड, ऐसेट केयर ऐंड रीकंस्ट्रक्शन एंटरप्राइज, सीएफएम एआरसी, इन्वेंट एआरसी, रेयर एआरसी और इंटरनैशनल ऐसेट रीकंस्ट्रक्शन कंपनी से मिले।

होम फाइनैंस कंपनी के लिए ईओआई सौंपने की आखिरी तारीख 15 सितंबर है।

आरसीएफएल 11,000 करोड़ रुपये की एयूएम वाली एनबीएफसी है जबकि रिलायंस होम फाइनैंस की एयूएम 14,500 करोड़ रुपये से अधिक की है।

5 अगस्त को रिलायंस होम फाइनैंस ने कहा था कि लिक्विड म्युचुअल फंड में निवेश के तौर पर उसके पास 800 करोड़ रुपये से ज्यादा की शुद्ध नकदी है। लेकिन ऋण अदायगी में विलंब दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए 20 नवंबर 2019 के आदेश के बाद किसी तरह की परिसंपत्तियों के कब्जे के संबंध में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से रोक की वजह से हुआ है।

विवाद पर एक नजर

- आरसीएफएल, आरएचएफएल बैंक ऋण चुकाने में विफल रहीं
- प्रमुख ऋणदाता बीओबी ने आरबीआई से कहा कि आरसीएफएल, आरएचएफएल को एनसीएलटी में भेजा जाए
- बीओबी यह भी चाहता है कि फॉरेंसिक ऑडिट के बाद आरसीएफएल, आरएचएफएल को फ्रॉड अकाउंट के तौर पर घोषित किया जाए
- दिल्ली उच्च न्यायालय ने दोनों कंपनियों को अगली सुनवाई तक फ्रॉड अकाउंट घोषित किए जाने की बीओबी की पहल पर रोक लगा दी

एजीआर पर इस हफ्ते न्यायालय का फैसला

मेघा मनचंदा
नई दिल्ली, 30 अगस्त

समायोजित सकल राजस्व पर दूरसंचार उद्योग सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का इंतजार कर रहा है, जो इस हफ्ते आ सकता है। एजीआर बकाए के भुगतान की समयसीमा में नरमी के अलावा सर्वोच्च न्यायालय के फैसले से वोडाफोन आइडिया के भविष्य का पता लग सकता है।

यह कंपनी बढ़ते नुकसान से जूझ रही है और इस मामले पर सर्वोच्च न्यायालय का फैसला आने के बाद वह भविष्य की रूपरेखा तय कर सकती है। दूरसंचार विभाग ने कंपनी की तरफ से एजीआर बकाए पर 20 साल की समयसीमा की मांग की थी, जिसे न्यायालय ने ठुकरा दिया था।

केएस लीगल ऐंड एसोसिएट्स की मैनेजिंग पार्टनर सोनम चंदवानी ने कहा, अगर सर्वोच्च न्यायालय पुनर्भुगतान के लिए 15 साल की समयसीमा पर फैसला लेता है तो यह कर्ज में फंसी वोडाफोन आइडिया के लिए चुनौती पेश करेगा। ऐसे खर्च के भुगतान के लिए ज्यादा टैरिफ, लागत में बचत और इक्विटी पूंजी निवेश की दरकार होगी। साथ ही ज्यादातर वित्तीय संस्थान वोडाफोन आइडिया को बड़ी रकम देने से परहेज कर सकते हैं।

हालांकि कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि स्पेक्ट्रम भुगतान में 20 साल की मोहलत वोडाफोन के अस्तित्व को थोड़ा बचा सकता है जब टैरिफ बढ़े और विनिवेश आगे बढ़े। हालांकि अगली कुछ तिमाहियों में गंवा चुके ग्राहकों को दोबारा पाना चुनौती हो सकती है। वोडाफोन व भारती ने भुगतान के लिए 15 साल की समयसीमा मांगी थी। सर्वोच्च न्यायालय इस पर फैसला लेगा।

न्यायालय के सामने एक अन्य मसला कंपनी के पास मौजूद स्पेक्ट्रम लाइसेंस की अवधि का भी है। कानूनी विशेषज्ञों ने कहा कि अगर लाइसेंस खत्म होता है तो पिछले बकाए की देनदारी खत्म नहीं होगी, खास तौर से अगर वह वैधानिक या सांविधिक देनदारी है।

सर्वोच्च्य न्यायालय ने 24 अगस्त को एजीआर पर सुनवाई पूरी कर ली थी।

नए ऑर्डरों से जुड़ी गतिविधियों में बीत गई दूसरी तिमाही

हालांकि निष्पादन संबंधी चुनौतियां अभी भी हैं बरकरार

अमृता पिल्लई
मुंबई, 30 अगस्त

पूंजीगत सामान एवं इंजीनियरिंग क्षेत्र के लिए जुलाई महीने में टेंडर जारी करना एवं परियोजनाएं आवंटित करने जैसी गतिविधियां पिछले साल के मुकाबले लगभग दोगुनी रहीं। हालांकि इस तेजी के बाद भी, विशेषज्ञों का कहना है कि नए ऑर्डरों एवं उनके अनुपालन के लिहाज से सितंबर तिमाही भी काफी कठिन रहेगी।

सालाना आधार पर इन आंकड़ों में तेजी का अहम कारण पिछले साल चुनावों के चलते गतिविधियों में कमी रहना है। कुछ लोगों का यह भी मानना है कि नए ऑर्डरों के मामले में हालिया तिमाही का प्रदर्शन मार्च एवं जून तिमाही के मुकाबले काफी बेकार रहा। साथ ही, इस साल के शेष समय के लिए भी नए ऑर्डर सड़क एवं जल जैसे क्षेत्रों तक ही सीमित रहने के आसार हैं।

एमकी रिसर्च के अनुसार, पूंजीगत सामान एवं इंजीनियरिंग क्षेत्र के लिए टेंडरिंग गतिविधियां पिछले एक महीने में 120 प्रतिशत बढ़ी हैं और सालाना आधार पर दोगुनी हुई हैं। रेटिंग एजेंसी इक्रा ने एक हालिया रिपोर्ट के अनुसार, सड़क परियोजनाओं में वर्तमान वित्त वर्ष के पहले चार महीनों में पिछले साल के मुकाबले 166 प्रतिशत की तेजी दर्ज हुई है।

हालांकि पिछले साल चुनावी वर्ष होने के चलते इन सभी एजेंसियां द्वारा लिए गए पिछले वर्ष के आंकड़े सामान्य से कम रहे थे। एमकी की रिपोर्ट के अनुसार, जुलाई में जारी किए गए अधिकांश ऑर्डर सड़क, रेलवे, जल एवं रियल एस्टेट क्षेत्र से आए। हालांकि रिपोर्ट बताती है कि क्रमिक आधार पर यह संख्या निराशाजनक है और बारह महीनों में आवंटन एवं आदेशों को अंतिम रूप देना अभी भी 28 प्रतिशत कम है।

कर्ज पुनर्गठन की ओर मायल के कदम

अभिजित लेले
मुंबई, 30 अगस्त

महामारी के प्रसार को रोकने के लिए लगाए गए प्रतिबंधों के चलते गंभीर स्तर पर प्रभावित होने वाले क्षेत्रों में विमानन एवं संबंधित गतिविधियां शामिल रहीं

भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा कोरोना से प्रभावित क्षेत्रों तथा उद्यमों के लिए जारी विशेष प्रावधानों के तहत कर्जदाता जीवीके समूह की इकाई मुंबई इंटरनैशनल एयरपोर्ट्स लिमिटेड (एमआईएएल) का कर्ज पुनर्गठन कर सकते हैं।

कोरोना महामारी के प्रसार को रोकने के लिए लगाए गए प्रतिबंधों के चलते गंभीर स्तर पर प्रभावित होने वाले क्षेत्रों में विमानन एवं संबंधित गतिविधियां शामिल रहीं।

एक निजी बैंक के वरिष्ठ अधिकारी ने एमआईएएल के बारे में बात करते हुए कहा कि कोविड-19 से प्रभावित हवाई अड्डों के पुनर्गठन की आवश्यकता है। यह एक उचित प्रक्रिया के तहत होना चाहिए, क्योंकि कर्ज काफी अधिक है। हमें के.वी. कामत समिति की अनुशंषाओं का इंतजार करना चाहिए और इसके बाद कर्जदाता पुनर्गठन पर बातचीत करेंगे। एमआईएएल पहले ही आरबीआई द्वारा कोरोना से होने वाले प्रभाव के कारण भुगतान पर दी गई मोरेटोरियम सुविधा का लाभ उठा चुका है।

रिजर्व बैंक ने कोरोना महामारी के कारण तनाव झेल रहे कारोबारी उधारकर्ताओं के कर्ज पुनर्गठन पर सलाह देने के लिए के.वी. कामथ की अध्यक्षता में एक समिति गठित की है। उम्मीद है कि समिति विभिन्न पैमानों का अनुसरण करके वास्तवित में प्रभावित उद्यमों का पता लगाने लिए मानक निर्धारित करेगी तथा जरूरी सहायता की अनुसंशा करेगी।

वर्ष 2017 में एयरपोर्ट इन्फ्रास्ट्रक्चर कंपनी ने अपने बैंकर्स कंसोर्टियम के साथ मिलकर 10,600 करोड़ रुपये से ज्यादा के कर्ज का पुनर्गठन किया था।

सरकारी क्षेत्र के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि हवाई अड्डों पर होने वाली आय के दो प्रमुख स्रोत (किराए पर दी जाने वाली जमीन एवं रिलेट आउटलेट पर बिक्री) महामारी से बुरी तरह प्रभावित हुई है। इसमें सुधार आने में भी बहुत समय लगेगा जो अर्थव्यवस्था को प्रभावित करेगा। उधारकर्ताओं द्वारा कर्ज पर दोबारा काम करना एक विकल्प हो सकता है।

अधिकारी ने बताया कि कोरोना से बुरी तरह प्रभावित होने वाले तीन प्रमुख क्षेत्रों में विमानन, पर्यटन एवं यात्रा तथा हॉस्पिटैलिटी शामिल हैं।

इस महीने की शुरुआत में, रेटिंग एजेंसी क्रिसिल ने 350 करोड़ रुपये के टर्म लोन के चलते मुंबई इंटरनैशनल एयरपोर्ट्स लिमिटेड की रेटिंग 'बी' से घटाकर 'सी' कर दी थी। क्रिसिल ने परियोजनाओं के लिए कर्ज समेत बकाया बैंक कर्ज सुविधाओं के लिए भी रेंटिंग में कमी की थी। कंपनी की रेटिंग 'नकारात्मक प्रभावों के साथ रेंटिंग पर निगरानी' मानक पर है।

परियोजनाओं तथा एडीएफ कर्ज के लिए रेटिंग में कमी आगामी समय में कर्ज आवश्यकताओं के मुकाबले नगदी प्रवाह की कम उपलब्धता को दर्शाती है।

साथ ही, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआई) को सालाना रियायत शुल्क के भुगतान के संबंध में दिल्ली उच्च न्यायालय में लंबित निर्णय के कारण एस्क्रो खाते में नगदी शेष के उपयोग को लेकर भी अनिश्चितता है।

एमआईएएल के पास सितंबर 2020 में परियोजना संबंधी कर्ज को लेकर लगभग 65 करोड़ रुपये के ऋण सेवा दायित्व हैं। इसके अलावा, मार्च से अगस्त 2020 तक की अवधि के लिए लगभग 147 करोड़ रुपये के अर्जित ब्याज के उपचार पर सीमित दृश्यता है। क्रिसिलि का कहना है कि मोरेटोरियम समय के दौरान कुल ब्याज 293 करोड़ रुपये रहा जिसमें भारतीय स्टेट बैंक ने लगभग 146 करोड़ रुपये के अर्जित ब्याज के अपने हिस्से को मूलधन में जोड़ा है।

होटल, मल्टीप्लेक्स, रिटेल शेयरों में नरम पड़ी तेजी

श्रीपाद ऑटे
मुंबई, 30 अगस्त

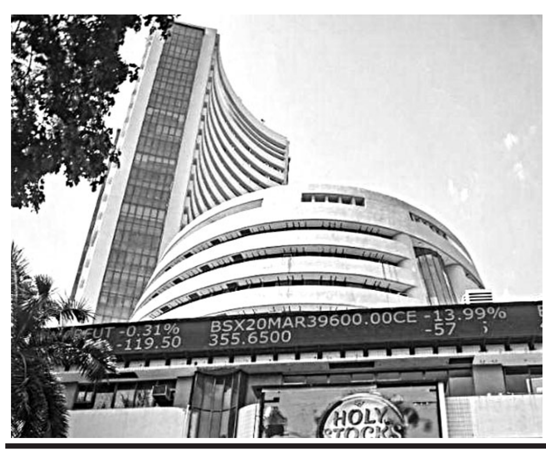

- इन क्षेत्रों में कई शेयर पिछले तीन महीनों में 30-100 प्रतिशत चढ़े हैं, जो बीएसई के सेंसेक्स में आई 26.5 प्रतिशत की तेजी के मुकाबले ज्यादा है
- कुछ विश्लेषकों का कहना है कि यदि लॉकडाउन से संबंधित सख्ती हटा ली जाती है तो भी परिवारों की आर्थिक स्थिति में तुरंत सुधार नहीं आएगा।

लॉकडाउन से संबंधित सख्ती में धीरे धीरे दी जा रही नरमी से होटल, रिटेल और मल्टीप्लेक्स जैसे क्षेत्रों के शेयरों में धारणा सुधरी है, जो कोविड-19 महामारी से बुरी तरह प्रभावित हुए थे। इन क्षेत्रों में कई शेयर पिछले तीन महीनों में 30-100 प्रतिशत चढ़े हैं, जो बीएसई के सेंसेक्स में आई 26.5 प्रतिशत की तेजी के मुकाबले ज्यादा है।

इसे लेकर कोई संदेह नहीं है कि हालात अब पिछले तीन-चार महीनों की तरह खराब नहीं हैं और बाजार अब वित्त वर्ष 2021 के वित्तीय प्रदर्शन से परे देख रहा है। हालांकि, प्रमुख सवाल यह है कि क्या तेजी बरकरार रहेगी।

इक्विनोमिकस रिसर्च ऐंड एडवायजरी के संस्थापक जी चोकालिंगम के अनुसार, 'हमारा मानना है कि रिटेल, होटल और मल्टीप्लेक्स जैसे क्षेत्रों के शेयरों में तेजी बरकरार रहने की संभावना नहीं है। बाजार दो प्रमुख पहलुओं - महामारी के दौरान नुकसान की वजह से बैलेंस शीट पर दबाव और प्रतिफल में संभावित विलंब की स्थिति सामान्य होने - को नजरंदाज कर रहा है।'

सिस्टमैटिक्स ग्रुप में संस्थागत शोध के निदेशक एवं प्रमुख धनंजय सिन्हा ने भी इसी तरह के विचार प्रकट करते हुए कहा, 'हालात अब बेहतर हो सकते हैं। लेकिन हमारा मानना है कि होटल, रिटेल और मल्टीप्लेक्स जैसे क्षेत्रों पर दबाव बना रहेगा और वे संपूर्ण बाजार के मुकाबले कमजोर प्रदर्शन करेंगे। हम बैंकिंग या ऑटोमोबाइल एंसिलियरी स्पेस से अन्य शेयरों को पसंद कर रहे हैं जिनमें आय संभावना और मूल्य वृद्धि अपेक्षाकृत अच्छी है।'

कुछ विश्लेषकों का कहना है कि यदि लॉकडाउन से संबंधित सख्ती हटा ली जाती है तो भी परिवारों की आर्थिक स्थिति में तुरंत सुधार नहीं आएगा। इसके अलावा, सामाजिक आयोजन कम होने और लोगों द्वारा भीड़ भाड़ वाले या सार्वजनिक स्थानों पर जाने से परहेज करने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। इसका इन क्षेत्रों की व्यावसायिक वृद्धि पर प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ेगा।

हालांकि होटलों के मामले में, लॉकडाउन पूरी तरह हटा लिया गया है, लेकिन इनमें ऑक्यूपेंसी यानी ग्राहकों की आवाजाही बढ़ने में समय लगेगा। आईडीबीआई कैपिटल में विश्लेषक अर्चना गुडे का कहना है, 'आय संभावना होटलों के लिए काफी कमजोर है, हालांकि सितंबर तिमाही में सुधार दिखने की संभावना है। इसलिए जब तक आय संभावना नहीं दिखती, तब तक होटल कंपनियों के शेयरों के लिए अपने मूल्यांकन मल्टीपल पर फिर से पहुंचने के आसार नहीं दिख रहे हैं।'

रिटेलरों के लिए, भौगोलिक मिश्रण और उत्पाद पोर्टफोलियो की प्रकृति मुख्य निर्णायक कारक हैं। एलारा कैपिटल के विश्लेषक अखिल पारेख ने कहा कि उदाहरण के लिए, वी-मार्ट जैसे शेयर अर्द्ध-शहरी और ग्रामीण इलाकों के लिए अपने ज्यादा कारोबार को देखते हुए बेहतर स्थिति में रहेंगे, जबकि ट्रेंट और आदित्य बिड़ला फैशन ऐंड रिटेल (जिनकी टियर-1/शहरी इलाकों में अच्छी उपस्थिति है) जैसी कंपनियों पर दबाव बना रहेगा। एवेन्यू सुपरमार्ट्स जैसे जरूरी उपभोक्ता वस्तु रिटेलरों पर अपैरल और लक्जरी सामान की बिक्री करने वालों की तुलना में कम प्रभाव पड़ने का अनुमान है।

मल्टीप्लेक्स के मामले में, हालांकि कुछ विश्लेषकों ने सकारात्मक रुख अपनाया है, लेकिन उनमें दर्शकों की आवक ओवर-द-टॉप प्लेटफॉर्मों के लिए बढ़ती पसंद से प्रभावित होगी। इसके अलावा कंटेंट रिलीज में विलंब और फूड एवं बेवरेज सेगमेंट में कम मांग अन्य प्रमुख चुनौतियां हैं।

सार्वजनिक सूचना

सर्वसाधारण को यह सूचित किया जाता है कि राजनीतिक दल मक्कल नला कड़गम के नाम से रजिस्ट्रीकृत होना प्रस्तावित है। पार्टी कार्यालय नं.30, वार्ड 2, नेताजी नगर, तातनावलासइ, कोडुम्पली पोस्ट, तिरूपत्तूर (तालूक/ जिला), तमिलनाडु-635653 में स्थित है। इस दल ने लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 29क के अधीन राजनीतिक दल के रूप में रजिस्ट्रीकरण के लिए भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली को आवेदन प्रस्तुत किया है - पार्टी के पदाधिकारियाँ के नाम/पता नीचे दिए गए है :-

सभापति/अध्यक्ष : एस.सत्यमुरती.
30, वार्ड 2, नेताजी नगर, तातनावलासइ, कोडुम्पली पोस्ट,
तिरूपत्तूर (तालूक/ जिला), तमिलनाडु-635653

महासचिव : पी.शिवकुमार
216, वीरापल्ली, सोमनईकनपट्टी,
तिरूपत्तूर (तालूक/ जिला), तमिलनाडु-635653

कोषाध्यक्ष : एल.करीबीरन
102 ऐ. मदापल्ली, तिरूपत्तूर (तालूक/ जिला), तमिलनाडु-635653

यदि किसी को मक्कल नला कड़गम के रजिस्ट्रीकरण में काई आपति हो तो अपनी आपती इसके कारणों सहित सचिव (राजनीतिक दल) भारत निर्वाचन आयोग निर्वाचन सदन, अशोक रोड़, नई दिल्ली - 110001 को, इस सूचना के प्रकाशन के 30 दिनों के भीतर भेजें।

SHAKTI®
PUMPING LIFE

शक्ति पम्पस् (इंडिया) लिमिटेड

सीआईएन : L29120MP1995PLC009327
पंजीकृत कार्यालय : प्लॉट नं. 401, 402 एवं 413, सेक्टर-III, इण्डस्ट्रीयल एरिया, पीथमपुर, जिला धार (म.प्र.)-454 774 फोन: 07292-410500, फैक्स: 07292-410645
ई-मेल : cs@shaktipumpsindia.com, वेबसाईट : www.shaktipumps.com

वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग/अन्य ऑडियो विजुअल माध्यम से आयोजित होने वाली 25वीं वार्षिक साधारण सभा की सूचना

एतद् द्वारा यह सूचना दी जाती है कि एजीएम की सूचना में बताये जाने वाले व्यवसाय को सम्पादित करने के लिए कंपनी के सदस्यों की 25वीं वार्षिक साधारण सभा ('एजीएम') का आयोजन 29 सितम्बर 2020 को दोपहर 12.30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग/ अन्य ऑडियो विजुअल माध्यम ("VC/OAVM") से आयोजित की जायेगी। एजीएम में प्रस्तावित होने वाले व्यवसायों की सूचना एजीएम के नोटिस दिनांक 05 अगस्त 2020 में दी गई है।

कंपनी अधिनियम, 2013 के लागू प्रावधानों और कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय द्वारा दिनांक 08 अप्रैल, 2020 को जारी परिपत्र संख्या 14/2020, दिनांक 13 अप्रैल, 2020 को जारी परिपत्र संख्या 17/2020 और दिनांक 05 मई, 2020 को जारी परिपत्र संख्या 20/2020 एवं भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) द्वारा दिनांक 12 मई 2020 को जारी परिपत्र क्रमांक SEBI / HO / CFD / CMD1 / CIR / P / 2020 / 79 जो एक स्थल पर सदस्यों की भौतिक उपस्थिति के बिना VC/OAVM के माध्यम से एजीएम करने की अनुमति देते हैं, के अनुपालन में एजीएम को VC/OAVM से आयोजित किया जायेगा। सदस्यों को सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड (सीडीएसएल) द्वारा प्रदान किए गए इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म के माध्यम से एजीएम में भाग लेने की सुविधा प्रदान की जाएगी।

उपरोक्त परिपत्रों के अनुपालन में, एजीएम की सूचना तथा वार्षिक रिपोर्ट वर्ष 2019-2020 की इलेक्ट्रॉनिक कॉपी उन सभी शेयरधारकों को भेजी जायेगी, जिनके ईमेल आईडी कंपनी/ डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स के पास पंजीकृत हैं। यदि आपने कंपनी/ डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स के साथ अपना ईमेल आईडी पंजीकृत नहीं किया है, तो कृपया आप अपने ईमेल आईडी को पंजीकृत/ अपडेट करने के लिए नीचे दिये गए निर्देशों का पालन करें।

भौतिक पद्धति	ईमेल आईडी पंजीकृत करने के लिए कृपया कंपनी/ रजिस्ट्रार एंड शेयर ट्रांसफर एजेंट को ईमेल द्वारा फोलियो नंबर, शेयरधारक का नाम, शेयर सर्टिफिकेट (फ्रंट एंड बेक) की स्केन कॉपी, पेन कार्ड और ड्रायविंग लाइसेंस, चुनाव पहचान पत्र, आधार कार्ड या पासपोर्ट में से किसी एक की स्व-प्रमाणित कॉपी के साथ अनुरोध करें।
डीमेट पद्धति	कृपया अपने डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स (डीपी) से संपर्क करें और आपके डीपी द्वारा बताए अनुसार अपना ईमेल आईडी एवं बैंक खाते को पंजीकृत करें।

सदस्य ध्यान दें कि 25वीं एजीएम की सूचना तथा वार्षिक रिपोर्ट 2019-20 कंपनी की वेबसाइट www.shaktipumps.com और स्टॉक एक्सचेंज बीएसई लिमिटेड की वेबसाइट www.bseindia.com और एनएसई की वेबसाइट www.nseindia.com पर उपलब्ध रहेगी। 25वीं एजीएम की सूचना सीडीएसएल की वेबसाइट www.evotingindia.com पर भी उपलब्ध रहेगी।

सदस्यों को एजीएम सूचना में बताए गए व्यवसाय पर एजीएम से पहले और एजीएम के दौरान अपने मतदान कर इलेक्ट्रॉनिक रूप से क्रमशः रिमोट ई-वोटिंग और ई-वोटिंग के माध्यम से उपयोग करने का अवसर भी उपलब्ध कराया जायेगा। भौतिक रूप से शेयर रखने वाले और जिन सदस्यों ने कंपनी के साथ अपनी ईमेल आईडी को पंजीकृत नहीं किया है उनके लिए एजीएम से पहले एजीएम के दौरान क्रमश रिमोट ई-वोटिंग और ई-वोटिंग के लिए विस्तृत प्रक्रिया को एजीएम सूचना में उपलब्ध कराया जायेगा।

उपरोक्त जानकारी कंपनी के सभी सदस्यों की जानकारी और लाभ के लिए जारी की जा रही है और एमसीए परिपत्र और सेबी परिपत्र के अनुपालन में है।

बोर्ड के आदेश से
द्वारा **शक्ति पम्पस (इंडिया) लिमिटेड**
रवि पाटीदार
कंपनी सचिव
ए.सी.एस. A32328

दिनांक: **30 अगस्त 2020**
स्थान: **पीथमपुर**

बिज़नेस स्टैंडर्ड
भोपाल संस्करण

बिज़नेस स्टैंडर्ड प्राइवेट लिमिटिड के लिए प्रकाशक एवं मुद्रक नंदन सिंह रावत द्वारा नई दुनिया न्यूज़ ऐंड नेटवर्क प्राइवेट लिमिटेड, 23/4-23/5, गोविंदपुरा इंडस्ट्रियल एरिया, सेक्टर-डी, सीपेट हॉस्टल के पास, भोपाल, म.प्र. 462011 से मुद्रित एवं मानव निकेत, प्रथम तल, प्लॉट नं. 30, इंदिरा प्रेस कॉम्प्लेक्स, एम पी नगर, ज़ोन-1, भोपाल, म.प्र. 462011 से प्रकाशित
संपादकः कैलाश नौटियाल

आरएनआई न० MPHIN/2008/24603
पाठक संपादक को **lettershindi@bsmail.in** पर संदेश भेज सकते हैं1
टेलीफोन- 0755-4064605-7 फैक्स -0755-4064670
सब्सक्रिप्शन और सर्कुलेशन के लिए कृपया सम्पर्क करें..
सुश्री मानसी सिंह
हेड कस्टमर रिलेशन्स
बिज़नेस स्टैंडर्ड प्राइवेट लिमिटेड, एच/4 एवं आई/3, बिल्डिंग एच, पैरागन सेंटर, बिड़ला सेंचुरियन के सामने, पी बी मार्ग, वर्ली, मुंबई-400013
ई मेल.. **subs_bs@bsmail.in**
या 57007 पर एसएमएस करें **SUB BS**

डिस्क्लेमर.. बिज़नेस स्टैंडर्ड में प्रकाशित समाचार रिपोर्ट और फीचर लेखों के माध्यम से बाजारों, कॉर्पोरेट जगत और सरकार से जुड़ी घटनाओं की निष्पक्ष तस्वीर पेश करने का प्रयास किया जाता है1 बिज़नेस स्टैंडर्ड के नियंत्रण एवं जानकारी से परे परिस्थितियों के कारण वास्तविक घटनाक्रम भिन्न हो सकते हैं। समाचार पत्र में प्रकाशित रिपोर्टों के आधार पर पाठकों द्वारा किए जाने वाले निवेश और लिए जाने वाले कारोबारी निर्णयों के लिए बिज़नेस स्टैंडर्ड कोई जिम्मेदारी नहीं लेता है। पाठकों से स्वयं निर्णय लेने की अपेक्षा की जाती है।
बिज़नेस स्टैंडर्ड के सभी विज्ञापन सद्भाव में स्वीकार किए जाते हैं। इनके साथ बिज़नेस स्टैंडर्ड न तो जुड़ा हुआ है और न ही उनका समर्थन करता है। विज्ञापनों से संबंधित किसी भी प्रकार का दावा संबंधित विज्ञापनदाता से ही किया जाना चाहिए।
मै0 बिज़नेस स्टैंडर्ड प्रा0 लि0 का सर्वाधिकार सुरक्षित है। बिजनेस स्टैंडर्ड प्रा0 लि0 से लिखित अनुमति लिए बगैर समाचार पत्र में प्रकाशित किसी भी सामग्री का किसी भी तरह प्रकाशन या प्रसारण निषिद्ध है। किसी भी व्यक्ति या वैधानिक निकाय द्वारा इस तरह का निषिद्ध एवं अनधिकृत कार्य करने पर दीवानी और फौजदारी कार्यवाही शुरु की जाएगी।

कोई हवाई अधिभार नहीं

Shah's lecture on Covid & Museums today

BHOPAL: A lecture on 'Will Covid make Museum accessible?' will be held on Monday. It is part of Museum popular lecture series, organised by Indira Gandhi Manav Sangrahalaya (IGRMS), Bhopal on its Facebook page. Siddhant Shah, Founder, Access for All will deliver the lecture. He is a Speaker, Inclusive Arts based Therapist, UNESCO consultant on accessibility and specializes in bridging the gap between cultural heritage, arts and with wellness and disability.

OVERHEARD

Trouble ahead

Probe agencies may soon turn their attention to an IPS officer. A complaint about an officer, very close to the Sahib, has been made to the central agency. In a few years, the officer posted to a corporation has bought huge properties disproportionate to his known sources of income. He has laid his hands on many farmhouses and lands near the state capital. The IPS officer has put in a lot of money in the properties bought by the officer. A video clip of a farmhouse of the officer was recently released. The video clip did not contain complete information about his properties. From the clip, however, it is clear that some people are after him. The Sahib has always enjoyed plum posting. When he was holding an important post, he made a huge amount of dough. A lot of information about him was secretly sent to the income-tax department. I-T department, which is inquiring into a benami property scam that has recently rocked the state capital, may soon take up the IPS officer's case.

Lure of lucre

A collector known for courting controversies has extorted huge amount of gravy. What is more, he is asking for dough from different people in the name of a BJP leader. The collector is openly demanding money from mining barons in the district. He says he has to give the brass to a senior BJP leader. The collector is damaging the reputation of the BJP leader concerned. The fed-up mining magnets have recorded his phone calls. In the audio clip, the collector is heard saying that, some BJP leaders are taking money from him, and he is getting little amount of it. Although collectors of most of the districts have been changed, nobody has understood the reasons for keeping this corrupt collector in the district. The officer has also won over the Congress leaders in the district so much, so that they do not raise their voice against him.

Plan to return

A senior IAS officer, on deputation to the Centre, plans to return to the state. The term of his deputation is still on, but his cooling period is about to end. Therefore, he may come back to the state after completing that period. Several things in the present state government are in his favour. He went to the Centre during the BJP rule because of some family problems. As his wife is working for the Central Government, he left for Delhi. He is holding an important position in the national capital, yet he is not happy. The state government needs good officers, because many of them have left for Delhi. Similarly, another senior IAS officer was deputed to the Centre a long time ago. But he is disinclined to return to the state. He has bolstered his clout in Delhi for staying there.

Cash collection

A feud over collection of brass among officials in a department, which is known for kicking up controversies, has deepened. There is a system of illegal dough collection in the department. The system functions in the BJP government as well as in the Congress administration. Now, the minister of the department wants to change the system, after much hue and cry over the collection. The minister is in no mood to relent. He has clearly told the officials that the department will be under his control, and that his aid will take the dosh. He called all the officers of the department, and told them to send all the rhino to his crony. Because of the minister's defiance, a solution to the problem the department is facing has yet to come out. The minister cracks the whip in the department. A top-rung officer chosen by him has been posted there. After the officer's posting, the minister has begun to bully the officials more than he did earlier.

Making moolah

Distribution of dough has kicked up a storm in a department that handles work worth crores of rupees. Many IAS officers have been transferred to the department in a few months. Because of continuous transfers, there has been bitterness among the officials over sharing lucre. A senior IAS officer has handed out a list of old accounts to a contractor who works for the department. The Sahib has also told the contractor that the gravy previously due to him should not go to anyone else. The contractor deals with the work of the department where the officer is posted. Therefore, the contractor can barely afford to pick a fight with the Sahib. A principal secretary, too, has extracted a huge amount of greenbacks from the contractor who has to get a lot of work done through the department. As new officers are posted there every now and then, the contractor is on the horns of a dilemma. An additional chief secretary-rung officer is controlling several things of the department from behind the scenes. So, to deal with the problems, the contractor has the ACS's backing.

Tortoise and rabbit

A minister and a principal secretary of an important department are behaving like the tortoise and the rabbit from the Aesop's Fables. On the one hand, the minister moves as fast as the rabbit from the fables does to finish all work. On the other hand, the principal secretary of the department works as slow as the tortoise from the tales does. The principal secretary does not take any decision in a hurry. She is not overenthusiastic about any work, and takes decisions only on important issues. As the attitude of the minister is very different from that of the PS, the department may soon turn into a bleak house. Otherwise also, the posting of an officer as part of the minister's personal staff has affected the functioning of the department. The officer is a man of the world. He is keen on everything, but for his own work.The minister may get a bad name in coming days because of her association with the officer.

■ **Nitendra Sharma**

22-year-old dies of lightning

OUR STAFF REPORTER
BHOPAL

A 22-year-old man died after lightning struck him in Gunga. His body was found near Dhamarra road on Sunday morning. The deceased Dharmendra Chouhan was a resident of Imlia village in Dhamarra. He worked at Aura mall in Shahpura.

He last spoke to his brother after he was stranded near an overflowing nulllah while returning from the work on Saturday evening. His brother asked him to stay there and wait till the water recedes. But he did not respond when his family tried to contact him little later. His body was found near the village by locals who informed police in the morning. The deceased had head injuries and burn marks. Police earlier suspected it to be a murder but short post mortem report indicated that he died as lightning struck.

Transportation issue puts NEET aspirants in a fix

Pvt buses are off roads as operators press for long pending demands

OUR STAFF REPORTER
BHOPAL

The National Eligibility-cum-Entrance Test (NEET) exam is scheduled to take place on September 13, but in the state the aspirants may not be able reach the exam centres as the deadlock between the government and the bus operators are not ending.

As the date of the exam is nearing, the non BJP state governments are appealing to extend the dates fearing the corona infections. And on the other side the BJP supported states are mum over the issue. But in Madhya Pradesh, one more problem is present, which is related to the means of transportation. The bus operators are not running their buses, they are demanding the government to waive off road tax from the months of March to August.

They had talked with the transport minister Govind Singh Rajput and finally with the chief minister Shivraj Singh Chouhan just two days back in Indore, but the result is yet to come.

In the state in five districts the exams are conducted Indore, Bhopal, Gwalior, Jabalpur and in Ujjain, the aspirants from all over the state choose their exam centres and reach to appear in the exam.

But this year along with the corona infections, the issue of bus operations is also a concern for them as well as for the parents.

The assistant transport commissioner Gunwant Sewantkar informed that the talks between the bus operators and the government are going and shortly the government will issue orders, redressing the operators' demand.

The private bus owners association Govind Sharma informed that people are contacting the bus operators to take their children to exam centres. But because of tax issues the buses are not operating, they have decided to not give the buses on rent, but if the government acquires the buses they will leave the students to the exam centres and also drop them back to their homes, on the humanitarian ground, said Sharma.•

Pandemic hits tourism hard, visits to sites down by 90%

Tourists to Mandu declines to 500 from over 3,000 per day

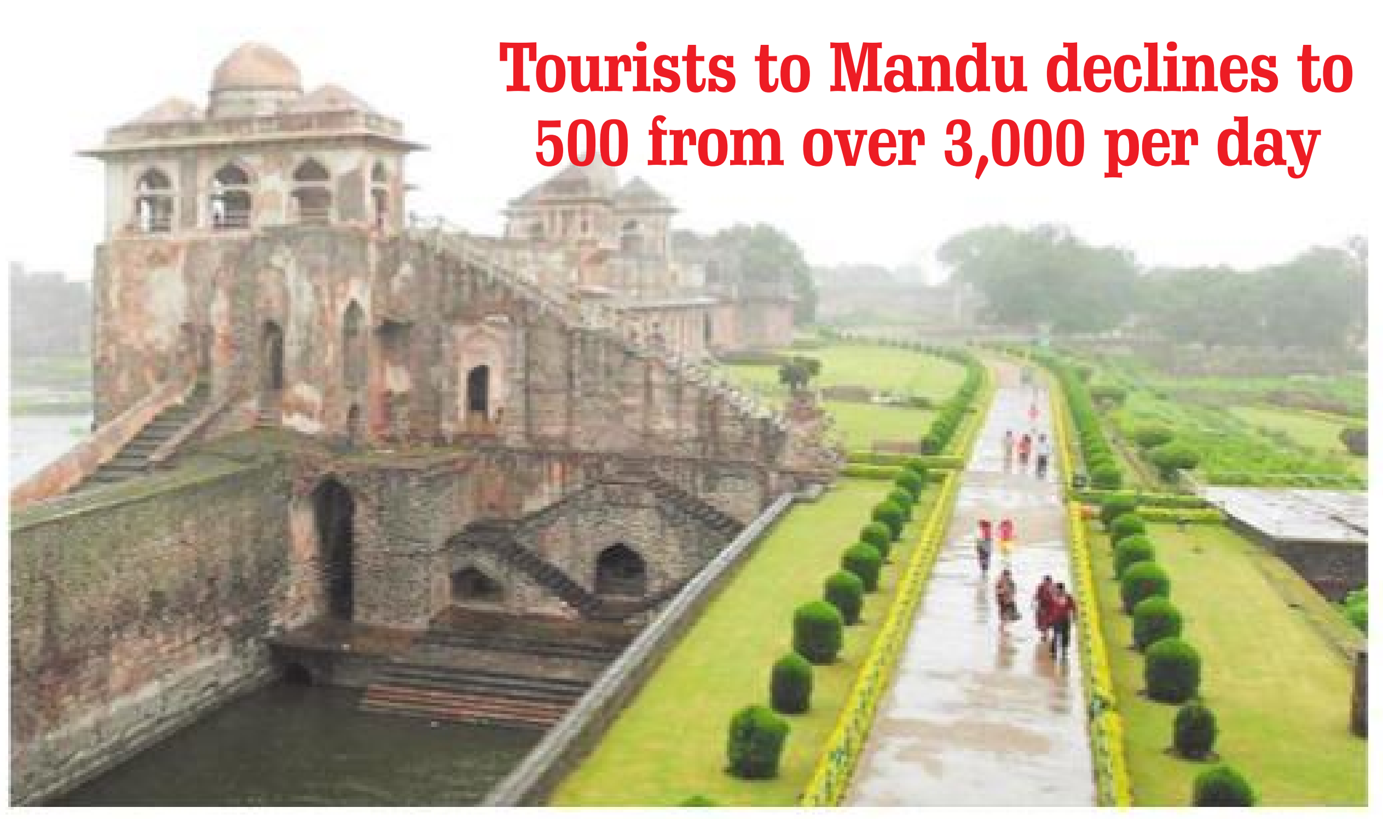

SMITA
BHOPAL

The number of tourists visiting the Archaeological Survey of India (ASI) -protected monuments in Madhya Pradesh has declined by up to 90% because of the corona pandemic.

Of the 290 ASI-protected monuments in the state, 60 'living monuments' were reopened on June 8 while others were reopened on July 6, after a gap of almost four months.

Before Covid, 4,000 to 5,000 tourists visited Mandu every day. That has now reduced to 500. Mandu has 61 monuments including Jahaz Mahal, Rani Roopmati Mahal, Baz Bahadur Mahal and Jama Masjid.

Conservation assistant, ASI, Mandu, Prashant, told Free Press that monsoon is the peak tourist season in Mandu. In pre-Covid times, 2000 to 3000 tourists visited the place on week days and 4000-5000 on Sundays. Now, the monuments are closed on Sundays due to lockdown.

Mandu is close to the state's borders with Rajasthan, Maharashtra and Gujarat and besides locals, tourists from these states are also coming to the place, he says. "We ensure that they follow all protection norms. We sanitise the monuments before closing them," Prasant says.

The footfalls at Bhimbetka, Bhojpur and Aadamgarh are down by 80%. Earlier, around 150 to 250 tourists used to visit these places every day but now the numbers have fallen to 25 to 50.

Against 700 earlier, only around 200 tourists are visiting Sanchi every day. The average footfall in Khajuraho before Covid -19 was 200 but now it is 60 to 70.

ASI Bhopal Circle, Superintending Archaeologist Piyush Bhatt says that the tourists are coming but their numbers are down. On an average, it is about 40 per cent of the earlier figures, he said.

Foreign tourists can't come as international flights are suspended. Even domestic tourists are mostly from the places around. Those from distant towns can't come because regular trains are not running and only a few flights are available. Even interstate buses are not running, he says. And then, of course, there is the fear of contracting the disease.

JABALPUR TO GET ASI CIRCLE

Madhya Pradesh will now have two ASI circles instead of one. Earlier the Bhopal circle of the ASI looked after the protected monuments in the entire state. Now, it has been decided to establish a new circle office at Jabalpur. The new circle will have jurisdiction over districts like Anuppur, Balaghat, Chhatarpur, Chhindwara, Damoh, Dindori, Jabalpur, Katni, Mandla, Panna, Rewa, Sagar, Satna, Seoni, Shahdol, Sidhi, Tikamgarh, Narsinghpur, Umaria, Singrauli and Niwari. The new office will become functional within the next two months.

Short film Ghungroo released

OUR STAFF REPORTER
Indore/ Mhow

The short film Ghungroo, directed by Richard Franklin from Mhow, is complete. The film's poster was released by Tourism Minister and MLA (Mhow) Usha Thakur on Sunday.

The film stars Anuradha Solanki, Nitya Yadav and Dinesh Solanki in the lead roles. Richard Franklin, who starred in a TV serial, has so far made documentary films on tourism. Ghungroo is his first directed film. This 9 minute 21 second film was released on YouTube on Sunday.

Ranka made School of Law head, Bansal director of DDL

OUR STAFF REPORTER
Indore

In a surprising move, Devi Ahilya Vishwavidyalaya (DAVV) vice chancellor Prof Renu Jain, who did not change any head in her more than one year of tenure, changed heads of three departments at a time when process of appointment of new VC is underway.

School of Law head Dr Manish Sitlani has been replaced with Dr Archana Ranka. Ranka had previously also was being head of School of Law.

After her, Sitlani was made head. However, Sitlani some months ago had expressed desired to leave the post and return to his parent department IIPS.

Accepting his "resignation", the VC relieved him from headship and appointed Ranka in his place.

Similarly, the VC shifted Directorate of Distance Education (DDL) director Prof Rajeev Gupta to School of Library Sciences and Central Library. He has replaced Ajay Kumar Sahani, who was incharge of both School of Library Sciences and Central Library.Given his experience, Gupta has been elevated. At DDL, Prof Pratosh Bansal has replaced him as director. A faculty with IETS< Bansal is also director of IQAC and chair of ODL committee.

West Discom data centre can now store data of 32 cr bills

OUR STAFF REPORTER
Indore

The data centre of Madhya Pradesh Western Region Power Distribution Company has been upgraded and now can store details of bills upto 32 crore.

Not only bill records but the centre can also store information on deposits, interest, surcharge, contributions of farmers' bills, photos of lakhs of meters, all 18 types of facilities of Urjas app and passbook of bills.

The data centre has been made a state-of-the-art facility. Jabalpur Electricity Company data centre has been connected to it for backup for security reasons.

West Discom managing director Amit Tomar said that the use of information technology will further enhance the facilities at the centre. "Currently, the data centre in Indore has a capacity of 64 tera bytes (TB). This will be further enhanced, so that the company's Urjas app can provide more facilities and features," he added.

Tomar said that the company will provide technically more facilities for all types of consumers like HT, LT, Agriculture, Industry, Domestic, Non Domestic, so that services can be further accelerated.

Five MP painters bag prizes at int'l contest

OUR STAFF REPORTER
BHOPAL

28 TO 30 AUG.
2020
AN ONLINE INTERNATIONAL
3rd ART
COMPETITION CUM EXHIBITION SHOW
Art

Five painters of Madhya Pradesh have won prizes at the three-day International online exhibition-cum competition 'I Paint' that concluded on Sunday. Art or Cause, Bhopal organised the exhibition to introduce the art and culture of different countries and also to provide a platform to artistes during Covid-19 pandemic. The artists of five countries showcased their works like 'Dallas Spring,' 'Fall, ' Flowers of the Sea,' 'Beach Story,' 'Prayer,' 'in the exhibition, appreciated by a viewers. Medals and certificates will be sent to the homes of the winners by post , said Faisal Mateen , organiser of the contest. The winners include: In Group-I first the prize went to Sahana Sunil Kumar of Chennai, second to Abdul Azeem Dourana of Guna and third: prize to Ibraheem Khan of Bhopal. In group-II, Tuba of Mumbai bagged the first prize, while the second and third went to Bhopal residents Arashi Shahid and Aamna Noor respectively. Group-III winners include Shabri Maheshwari (Vidisha), Yoo Choong Yeul• (Republic of Korea), Elham Badreddine Mahfouz (USA), Halime Ozcan• (Turkey). Silver Award: Naseem Jamil• (USA), Kim Moon Tae (Republic of Korea), Sahla Tello Kazziha (USA), Park Young Sil• (Republic of Korea).•

SHAKTI®
PUMPING LIFE
SHAKTI PUMPS (INDIA) LTD.
CIN : L29120MP1995PLC009327
Regd. Off.: Plot No. 401, 402 & 413, Sector III, Industrial Area,
Pithampur (M.P.)-454774 Ph.: 07292-410500, Fax: 07292-410645
Email : cs@shaktipumpsindia.com, Website: www.shaktipumps.com

Notice of 25th Annual General Meeting to be held through Video Conferencing / Other Audio Visual Means

NOTICE is hereby given that the 25th Annual General Meeting (AGM) of the Company will be held on 29th day September, 2020 at 12:30. P.M. IST through Video Conferencing / Other Audio Visual Means ("VC/OAVM") facility to transact the businesses that will be set forth in the Notice of AGM dated 05th August 2020.

The AGM will be held through VC/OAVM in Compliance with the applicable provisions of the Companies Act, 2013 read with Circular No. 14/2020 dated April 8, 2020, Circular No. 17/2020 dated April 13, 2020 and Circular No. 20/2020 dated May 5, 2020 Issued by Ministry of Corporate affairs and Circular No. SEBI / HO / CFD / CMD1 / CIR / P / 2020 / 79 dated May 12, 2020 issued by the Securities and Exchange Board of India (SEBI), permitting the holding of AGM through VC/OAVM without physical presence of members at a common venue. Members will be provided with a facility to attend the AGM through electronic platform provided by Central Depository Services (India) Limited (CDSL).

In compliance with the above Circulars, electronic copies of the Notice of AGM and Annual Report for the Financial Year 2019-20 will be sent to all the Shareholders whose email addresses are registered with the Company/ Depository Participant(s). If you have not registered your email address with the Company/ Depository Participant(s) you may please follow below instructions for registering/ updating your email addresses:

Physical Holding	Please send a request to the Company/ Registrar & Share Transfer Agent providing Folio No., Name of Shareholder, Scanned Copy of the Share Certificate (front and back), self attested copy of PAN Card and any of Driving License, Election Identity Card, Aadhar Card and Passport for registering email address.
Demat Holding	Please contact your Depository Participant (DP) and register your email address and bank account details as per process advised by your DP.

Members may note that the Notice of 25th AGM and the Annual Report for the Financial Year 2019-20 will be available on the Company's Website at www.shaktipumps.com and website of the Stock Exchanges i.e. BSE Limited at www.bseindia.com And NSE Limited at www.nseindia.com. The Notice of 25th AGM will also be available on the website of CDSL at www.evotingindia.com.

The members will have an opportunity to cast their vote electronically on the businesses set out in the AGM Notice through remote e-voting/ e-voting during the AGM. The detailed procedure of remote e-voting/ e-voting during the AGM by Members holding shares in Physicals mode and members, who have not registered their email ID with the Company, will be provided in the AGM Notice.

The above information is being issued for the information and benefit of all the Members of the Company and is in compliance with the MCA Circulars and SEBI Circular.

By order of the Board
For **Shakti Pumps (India) Limited**
Sd/-
Ravi Patidar
Company Secretary
ACS:-A32328

Date: **30th August, 2020**
Place: **Pithampur**

MOHINI
MOHINI HEALTH & HYGIENE LIMITED
Regd. Off: Plot No 109, Sector 3 Industrial Area,
Pithampur Dhar (M.P.) 454774
CIN:L17300MP2009PLC022058
Contact No.: +91-7292-426665, 7292-426666
E-mail:**sourabh@mohinifibers.com,**
Website: www.mohinihealthandhygiene.com

INFORMATION REGARDING 11TH ANNUAL GENERAL MEETING TO BE HELD THROUGH VIDEO CONFERENCE (VC) / OTHER AUDIO VIDEO VISUAL MEANS (OAVM)

1. Shareholders may please note that the 11th Annual General Meeting (AGM) of the Company will be held through VC / OAVM on Tuesday, 29th September, 2020 at 3.00 PM IST, in compliance with all the applicable provisions of the Companies Act, 2013 and the Rules made there under and the Securities and Exchange Board of India (SEBI) (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, read with General Circular No. 14/2020 dated 8th April, 2020, General Circular No. 17/2020 dated 13th April, 2020 and General Circular No. 20/2020 dated 5th May, 2020, and other applicable circulars as may be issued by the Ministry of Corporate Affairs (MCA), Government of India and SEBI in this regard, to transact the businesses that will be set forth in the Notice of the meeting.
2. In compliance with the above mentioned circulars, copy of the notice of the AGM and annual report of the Company for the financial year 2019-20 will be sent to all the Shareholders whose email addresses are registered with the Company / Depository Participant(s). The notice of the AGM and annual report for the financial year 2019-20 will also be available on the Company's website atwww.mohinihealthandhygiene.com and on the website of the National Stock Exchange at www.nseindia.com.
3. **Manner of registering/ updating email addresses:**
   * Shareholders holding shares in physical mode and who have not updated their email addresses with the Company are requested to update their email addresses by writing to the Company at cs@mohinihealthandhygiene.com along with the copy of the signed request letter mentioning the name and address of the Shareholder, self-attested copy of the PAN card and self-attested copy of any address proof of the Shareholder (eg: Driving License, Election Identity Card, Passport, Aadhar Card etc.) in support of the address of the Shareholder.
   * Shareholders holding shares in dematerialised mode are requested to register / update their email address with the relevant Depository Participants.
4. **Manner of casting vote through e-voting:**
   * Shareholders will have an opportunity to cast their votes remotely on the businesses as set forth in the Notice of the AGM through remote e-voting system.
   * The login credentials for casting the votes through e-voting shall be made available to the Shareholders through email after successfully registering their email addresses in the manner provided above.
   * The detailed procedure for casting the votes through e-voting shall be provided in the notice of the AGM. The details will also be made available on the website of the Company.
5. This notice is being issued for the information and benefit of all the Shareholders of the Company in compliance with the above mentioned circulars.

Place: Pithampur
Date: 31-08-2020

For Mohini Health & Hygiene Limited
Sd/-
Arnika Jain
Company Secretary